



# एग्री आर्टिकल्स

(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)

वर्ष: 04, अंक: 05 (सितंबर-अक्टूबर, 2024)

[www.agriarticles.com](http://www.agriarticles.com) पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

## विश्व खाद्य दिवस: खाद्य का अधिकार-एक बेहतर जीवन और एक बेहतर भविष्य के लिए

(\*ऑंचल खण्डेलवाल एवं डॉ. विमला डूंकवाल)

खाद्य एवं पोषण विभाग, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय,

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान-334006

\*संवादी लेखक का ईमेल पता: [khndelwalaanchal19@gmail.com](mailto:khndelwalaanchal19@gmail.com)

विश्व खाद्य दिवस की स्थापना 1979 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के 20वें सम्मेलन में हंगरी के पूर्व कृषि मंत्री डॉ. पॉल रोमनी द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के बाद हुई। इसे पहली बार 16 अक्टूबर 1981 को मनाया गया, और तब से यह हर साल 150 से अधिक देशों में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक भूख, कुपोषण और गरीबी को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है, ताकि सभी को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन प्राप्त हो सके। हर साल इस दिन के लिए एक नई थीम निर्धारित की जाती है, जो खाद्य सुरक्षा, कृषि, जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होती है। विश्व खाद्य दिवस 2024 की थीम "भोजन का अधिकार – एक बेहतर जीवन और एक बेहतर भविष्य के लिए" भोजन के मौलिक अधिकार को प्राथमिकता देती है और इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ भोजन मिल सके, जिससे एक न्यायसंगत, स्थायी और भूख मुक्त दुनिया की दिशा में प्रगति हो।



### खाद्य का अधिकार: एक मौलिक मानव अधिकार

खाद्य का अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) में निहित है, जो बताता है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक मानक जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन भी शामिल है। खाद्य का अधिकार केवल पर्याप्त कैलोरी की पहुंच तक सीमित नहीं है, यह सुरक्षित, पौष्टिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त भोजन की पहुंच को भी शामिल करता है, जो व्यक्तियों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने की अनुमति देता है।

खाद्य एवं कृषि संगठन इस बात को स्पष्ट करता है कि खाद्य सुरक्षा केवल एक आर्थिक या कृषि संबंधी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक और एथिकल दायित्व भी है। खाद्य का अधिकार सुनिश्चित करना इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, गरिमा के साथ भोजन प्राप्त कर सके। इस अधिकार पर ध्यान केंद्रित करके, यह विषय नीति निर्माताओं, समुदायों और व्यक्तियों को भूख, कुपोषण और खाद्य असमानताओं को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने में प्रेरित करता है।

### वैश्विक भूख और खाद्य असुरक्षा: एक स्थायी चुनौती

भोजन और कृषि में तकनीकी प्रगति के बावजूद, भूख और खाद्य असुरक्षा विश्वभर में आम समस्याएँ हैं। FAO की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 735 मिलियन लोग पुरानी भूख का सामना कर रहे हैं, जबकि लाखों अन्य कुपोषण के जोखिम में हैं। COVID-19 महामारी, चल रहे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक अस्थिरता ने वैश्विक खाद्य संकट को और भी बढ़ा दिया है, जिससे कमजोर आबादी को अधिक गहरी खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

विकसित क्षेत्रों में, खाद्य असुरक्षा अक्सर गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण होती है। वहीं, समृद्ध देशों में, खाद्य असुरक्षा विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों को प्रभावित करती है, जिनमें निम्न-आय वाले परिवार, आदिवासी समुदाय और ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्र शामिल हैं।



खाद्य का अधिकार इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए केंद्रित है। खाद्य एवं कृषि संगठन सरकारों, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आग्रह करता है कि वे खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि सभी नागरिकों को उचित पोषण प्राप्त हो। यह एक अनुस्मारक है कि भूख अनिवार्य नहीं है यह एक सुलझने योग्य समस्या है यदि राजनीतिक इच्छा, पर्याप्त संसाधन और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता हो।

### स्वास्थ्य और कल्याण पर खाद्य का प्रभाव

विषय "खाद्य का अधिकार – एक बेहतर जीवन और एक बेहतर भविष्य के लिए" भोजन और समग्र कल्याण के बीच के अंतर्निहित लिंक को उजागर करता है। पौष्टिक भोजन तक पहुंच शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए। कुपोषण, चाहे भूख से हो या खराब गुणवत्ता वाले आहार से, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसमें विकास में रुकावट, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और रोगों के प्रति बढ़ी संवेदनशीलता शामिल हैं।

विशेष रूप से बच्चों को कुपोषण से अत्यधिक प्रभावित किया जाता है। UNICEF के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में लगभग 45: मौतें कुपोषण से जुड़ी हैं। ये चिंताजनक आंकड़े यह दिखाते हैं कि सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों, को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए समग्र रणनीतियों की आवश्यकता है। एक बेहतर भविष्य स्वस्थ जनसंख्या की नींव पर आधारित है, इसलिए सभी के लिए खाद्य का अधिकार सुनिश्चित करना आवश्यक है।

साथ ही, खराब आहार की आदतें, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, गैर-संक्रामक बीमारियों (NCDs) जैसे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों के बढ़ते मामलों में योगदान कर रही हैं। विश्व खाद्य दिवस 2024 के हिस्से के रूप में, स्वस्थ, सतत आहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो दीर्घकालिक कल्याण का समर्थन करता है और स्वास्थ्य प्रणालियों के असफलता के बोझ को कम करता है।

### आर्थिक और सामाजिक समानता की ओर खाद्य का मार्ग

खाद्य असुरक्षा अक्सर सामाजिक और आर्थिक असमानता से जुड़ी होती है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों, जैसे कि छोटे किसान, आदिवासी लोग, महिलाएं और प्रवासी श्रमिक, अक्सर खाद्य और संसाधनों तक पहुंच को सीमित करने वाले प्रणालीगत अवरोधों का सामना करते हैं। इन जनसंख्या के लिए, खाद्य असुरक्षा अक्सर आर्थिक विषमताओं का परिणाम होती है, जिसमें भूमि, पानी और कृषि प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच शामिल है।

खाद्य का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए इन अंतर्निहित असमानताओं को संबोधित करना आवश्यक है। नीतियों को बढ़ावा देने से जो भूमि वितरण, उचित वेतन और किसानों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण तक पहुंच को समान रूप से प्रोत्साहित करती हैं, व्यक्तियों और समुदायों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सशक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कृषि में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं वैश्विक कृषि कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं लेकिन अक्सर उन्हें आवश्यक संसाधनों की कमी होती है।



खाद्य न्याय की वकालत करके, विश्व खाद्य दिवस यह दिखाता है कि खाद्य का अधिकार व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना समुदायों को सशक्त बनाता है, लिंग समानता को बढ़ावा देता है, और एक अधिक समावेशी, सुदृढ़ भविष्य में योगदान करता है।

### सतत कृषि: खाद्य सुरक्षा का आधार

खाद्य का अधिकार पूरी तरह से सतत कृषि प्रथाओं के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो पर्यावरण की रक्षा और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। कृषि अधिकांश लोगों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है, लेकिन अत्यधिक जल उपयोग, वन कटाई और रसायनिक प्रयोग पर अत्यधिक निर्भरता प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर रही हैं और जलवायु परिवर्तन में अवांछित योगदान दे रहे हैं।

खाद्य एवं कृषि संगठन सतत, पुनर्योजी कृषि प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो जैव विविधता को संरक्षित करती हैं, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करती हैं, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती हैं। एग्रोइकोलॉजी, पर्माकल्चर और जैविक खेती ऐसे उदाहरण हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करती हैं, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं, पानी का संरक्षण करती हैं, और खाद्य उत्पादन का पर्यावरणीय प्रभाव कम करती हैं।

सतत कृषि को बढ़ावा देकर, भविष्य की पीढ़ियों के लिए गृह के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा को पर्यावरणीय संरक्षण की नींव पर आधारित होना चाहिए ताकि भविष्य की जनसंख्या भी पर्यावरणीय क्षति के बिना खाद्य का अधिकार प्राप्त कर सके।

### सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका

खाद्य का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। सरकारों को अपनी राष्ट्रीय नीतियों में खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। कानूनों और नियमों को सख्ती से लागू करना चाहिए जो खाद्य के अधिकार की रक्षा करते हैं जिससे सभी नागरिकों को उचित पोषण सुनिश्चित हो सके। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, जैसे खाद्य सहायता कार्यक्रम, मिड डे मील और छोटे किसानों के लिए सब्सिडी, भूख और गरीबी को कम करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) जैसे संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं, जो भूख से लड़ने के वैश्विक प्रयासों का समन्वय करते हैं। ये संगठन आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करते हैं, कृषि विकास परियोजनाओं का समर्थन करते हैं, और नीतियों की वकालत करते हैं जो सतत खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देती हैं।

### निष्कर्ष

विश्व खाद्य दिवस 2024 का विषय, "खाद्य का अधिकार – एक बेहतर जीवन और एक बेहतर भविष्य के लिए", एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण केवल आर्थिक मुद्दे नहीं हैं बल्कि मानवीय और नैतिक दायित्व भी हैं। हर व्यक्ति को गरिमा के साथ भोजन प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। सतत कृषि, सामाजिक समानता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, हम एक न्यायपूर्ण और स्वस्थ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

### संदर्भ

1. FAO(2024). विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति। रोम, इटली
2. विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) (1996). विश्व खाद्य सुरक्षा पर रोम घोषणापत्र। रोम, इटली
3. संयुक्त राष्ट्र(1948). मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। संयुक्त राष्ट्र